मिश्र धातु निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
(मिनी रत्न कंपनी)
सुपर अलॉय्स प्लॉंट
निगमित पहचान सं. U14292TG1973GOI001660
डाकघर : कंचनबाग, हैदराबाद - 500 058. भारत
दूरभाष : 040-24184000 (श्रृंखला नं.)
फैक्स : 040-24340214, 24340280, 24340371
वेबसाइट : www.midhani.com

MIDHANI
AN ISO 9001:2008 COMPANY

MISHRA DHATU NIGAM LIMITED
(A. Govt. of India Enterprise)
(MINI RATNA COMPANY)
SUPERALLOYS PLANT
CIN: U14292TG1973GOI001660
P.O. Kanchanbagh, Hyderabad - 500 058. India
Phone : 040-24184000 (Extn.)
Fax : 040-24340214, 24340280, 24340371
Website : www.midhani.com

MDN/CS/BM-248/2019-20 Date: 18.05.2019

To,

The Manager,
Compliance Department,
Stock Exchange Mumbai, 1st Floor,
New Trading Ring, Rotunda Building
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400001

Scrip Code: BSE: 541195

The Manager,
Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor; Plot No. CII
G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400051

Scrip Code: NSE: MIDHANI

Sub: Intimation of date of Board Meeting to consider and approve, inter alia, Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2019 and also to consider recommendation of final Dividend for the FY 2018-19, if any.

Dear Sir,

1. We wish to inform that meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 29th May, 2019 to consider and approve, inter alia, Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2019 and also to consider recommendation of final Dividend for the FY 2018-19, if any.

2. For all Insiders the Trading window for dealing in securities of Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) is under closure from 04th April, 2019 and it is further notified that the Trading window will remain closed up to 31st May 2019 as per MIDHANI's "Code of Internal Procedures and Conduct for Prohibition of Insider Trading".

3. This is for your information and record.

Thanking You

Yours Faithfully,
For Mishra Dhatu Nigam Limited

Paul Antony
Company Secretary & Compliance officer

ग्रे सूची पर पाक को करनी होगी मेहनत

ईरान को सीधी चेतावनी दी डोनाल्ड ट्रंप ने

काला धन कानून पर सुनवाई आज

एफिल टॉवर परिसर कराया गया खाली

दो पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

सूखा निपटारा उपाय में देरी से न्यायालय खिन्न

अकबर का रमानी को होटल में बुलाने से इनकार

मिलाप बूथ

पुलिस

ट्रैफिक पुलिस

जीएचएमसी

अग्नि

हवाई अड्डा

बस स्टेशन (आईबीएस)

ऐक्शन में...

फ्लोर टेस्ट...

एक्जिट पोल ने...

प्रायश्चित शुरू...

आपत्तिजनक ट्वीट...

मुश्किल में...

ICAR-INDIAN INSTITUTE OF RICE RESEARCH

भाकृअनुप - भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान

निविदा सूचना

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

सूचना

भारत सरकार

उन्नत आंकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान (एड्रिन)

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना के लिए शुद्धिपत्र

क्लास एक्शन में बढ़ेंगी बिल्डरों की मुश्किलें

एम जे एंटनी

उच्चतम न्यायालय ने उपभोक्ता विवादों के संदर्भ में रियल एस्टेट कारोबार में क्लास एक्शन का दायरा बढ़ा दिया है। अंजुम हुसैन बनाम इंटेलिसिटी बिज़नेस पार्क लिमिटेड वाद में करीब 40 फ्लैट खरीदारों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की कि उन्होंने भुगतान कर दिया था लेकिन चार साल बाद भी उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया है और परियोजना अभी शुरुआती चरण में है। वे अपना पैसा वापस चाहते थे। बाद में उन्होंने अपनी शिकायत को उपभोक्ता संरक्षण कानून और नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत क्लास एक्शन में बदलने के लिए एक अर्जी लगाई। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में बन रही इस परियोजना में न केवल रिहायशी फ्लैट थे बल्कि दुकानें और दफ्तर भी बनने थे। राष्ट्रीय आयोग ने शिकायत को क्लास एक्शन में बदलने की अर्जी को खारिज कर दिया क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उन्हीं लोगों को उपभोक्ता माना गया है जो अपने इस्तेमाल के लिए सामान/सेवाएं खरीदते हैं। स्वरोजगार के अलावा अगर कोई व्यावसायिक उद्देश्य से संपत्ति खरीदता है तो वह उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि जिन सभी लोगों ने इस परियोजना में संपत्ति खरीदी वे इसका व्यक्तिगत इस्तेमाल करना चाहते थे और उनकी व्यावसायिक मंशा नहीं थी। अर्जी खारिज होने पर फ्लैट खरीदार उच्चतम न्यायालय पहुंचे। न्यायालय ने आयोग के आदेश को खारिज कर दिया और शिकायत को दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि अगर सभी लोगों की साझा शिकायत है तो उनकी तरफ से या उनके फायदे के लिए क्लास एक्शन याचिका दायर की जा सकती है। वे साझा राहत मांग सकते हैं और इस तरह वे एक ही सेवा प्रदाता के खिलाफ एक समुदाय हैं जिनका समान हित है।

श्रम मामलों में मूल कंपनी पक्ष नहीं

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी औद्योगिक विवाद के मामले में अगर सहयोगी कंपनी स्वतंत्र कॉरपोरेट इकाई है तो मूल कंपनी को स्वाभाविक रूप से पक्ष नहीं बनाया जा सकता है। ग्लोब ग्राउंड इंडिया एम्पलॉयीज यूनियन बनाम लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस वाद में सहयोगी भारतीय कंपनी हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और अनुषंगी सेवाएं दे रही थीं। उसने एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम बनाया जिनसे ग्राउंड हैंडलिंग के लिए एक और कंपनी बनाई। इस कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जो औद्योगिक पंचाट में पहुंच गए। वहां उन्हें नाकामी हाथ लगी और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहां भी उन्हें अनुकूल परिणाम नहीं मिला। वे चाहते थे कि उच्चतम न्यायालय इस विवाद में विमानन कंपनी को पक्ष बनाए। लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई सहयोगी कंपनी स्वतंत्र कॉरपोरेट इकाई है और दूसरी कंपनी शेयरधारक है तो यह मूल कंपनी को इस

अदालत से

विवाद में घसीटने का आधार नहीं है।

बीमा कंपनी को बतानी होंगी बहिष्करण की शर्तें

अगर किसी बीमा पॉलिसी में बहिष्करण की शर्तों के बारे में बीमित व्यक्ति को नहीं बताया गया है तो बीमा कंपनी दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने भारत वॉच कंपनी बनाम नैशनल इंश्योरेंस कंपनी वाद में अपने फैसले में यह बात कही। शोलापुर में घड़ियों के एक शोरूम में चोरी हो गई थी। शोरूम मालिक जिला फोरम में गया जिसने मुआवजा देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने भी इस आदेश को सही ठहराया। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शोरूम में जबरदस्ती घुसकर चोरी करने का कोई प्रमाण नहीं था। उसका कहना था कि अगर शोरूम में जबरदस्ती घुसकर चोरी की गई होती तो शोरूम मालिक मुआवजा पाने का हकदार होता। इस बारे में पॉलिसी में प्रावधान था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शोरूम के मालिक इस प्रावधान के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए यह वैध नहीं है। न्यायालय ने मुआवजे को सही ठहराया।

राज्य कानून पर भारी केंद्रीय मध्यस्थता कानून

कुछ राज्यों का अपना मध्यस्थता कानून है। इस स्थिति ये यह कानूनी सवाल पैदा हो गया है कि राज्य के कानून और केंद्र के मध्यस्थता एवं सुलह कानून के बीच विवाद पैदा हो सकता है। हाल में मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच मतभेद था और व्यापक पीठ ने इसका समाधान किया। पिछले सप्ताह यह मुद्दा एक बार फिर पटना उच्च न्यायालय में उठा। मामला कमलादित्य कंस्ट्रक्शंस बनाम बिहार राज्य वाद से जुड़ा था। राज्य का अपना बिहार सार्वजनिक कार्य अनुबंध विवाद मध्यस्थता पंचाट कानून है। पिछले साल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य के कानून के मुताबिक विभिन्न पक्षों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया राज्य पंचाट के सामने होनी चाहिए। ताजा फैसले में इसकी समीक्षा की गई और उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश को वापस लेते हुए कहा कि केंद्र का कानून लागू होगा। राज्य के कानून को 2008 में पारित किया गया था और उसे राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली है।

वनस्पति अर्क औषधि कानून के तहत

आंखों में धुंधलेपन और मधुमेह संबंधी रेटिना की बीमारी में काम आने वाली दवा बनाने वाली दो कंपनियों के बीच ट्रेड नाम ग्लोआई और ग्लोटैब को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा चला। इन दवाओं में वनस्पति अर्क होता है लेकिन उनकी सामग्री अलग-अलग होती है। खाद्य संरक्षा एवं मानक कानून के तहत इन्हें 'न्यूट्रास्यूटिकल्स' कहते हैं। सवाल यह था कि क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स आई ड्रॉप को फार्मास्यूटिकल्स माना जाए। चूंकि दोनों कंपनियों ने अपने ट्रेड मार्क को पंजीकरण कराया है इसलिए यह मामला 'पासिंग ऑफ' एक्शन में बदल गया। इस मामले में सन फार्मा लैबोरेट्रीज बनाम अजंता फार्मा वाद में दोनों कंपनियों की दवाओं के नाम 'ग्लो' से शुरू होता है। सन की दवा का नाम ग्लोआई और प्रतिद्वंद्वी दवा का नाम ग्लोटैब है। सन ने प्रतिद्वंद्वी कंपनी पर ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने उसके पक्ष में आदेश देते हुए प्रतिद्वंद्वी कंपनी के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में फार्मास्यूटिकल्स से जुड़े नियम लागू होंगे और इसमें उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। औषधि और दवा उत्पादों में भ्रम और धोखाधड़ी से बचा जाना चाहिए। आई और टैब ग्लोआई और ग्लोटैब में कोई अंतर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

स्कूली किताबों पर सीजीएसटी खत्म

कर अधिकारी कभी-कभी बाल की खाल निकालने लगते हैं। सोनका पब्लिकेशन बनाम भारत संघ वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में ऐसा ही देखने को मिला। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने बच्चों की पढ़ाई की किताबों पर पब्लिशर से छह फीसदी वस्तु एवं सेवा कर मांगा। अगर किसी नोट बुक में बच्चों की लिखावट सुधारने के लिए लाइनें हैं तो इस पर कर लगेगा। अगर किताब में सवाल हैं और छात्र को छोटे जवाब देने हैं या रिक्त स्थान भरना है तो यह वर्क बुक या प्रेक्टिस बुक बन जाती है जिसे कर में छूट हासिल है। इस मामले में राजस्व विभाग की दलील है कि वर्क बुक वास्तव असल में नोट बुक होती है जिस पर कर लगता है। न्यायालय ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि ये किताबें नोट बुक नहीं हैं और इन्हें जीएसटी नियमों में छूट हासिल है। न्यायालय ने कहा कि इसका मकसद बच्चे को खुद सोचने में मदद करना है ताकि शिक्षक उसका मूल्यांकन कर सके। यह नहीं कहा जा सकता है कि इन किताबों का मकसद लिखावट सुधारने के लिए शब्दों को कॉपी करना है।

बहीखाते की जांच में अंकेक्षकों की समस्या

सुदीप्त दे

ब्रिटेन की लेबर पार्टी के लिए ब्रिटिश शिक्षाविदों द्वारा तैयार रिपोर्ट (रिफॉर्मिंग द ऑडिटिंग इंडस्ट्री, दिसंबर 2018) में कहा गया है कि राज्य को वित्तीय क्षेत्र के लिए वैधानिक लेखांकन सेवाओं की पेशकश करने पर विचार करना चाहिए। विभिन्न देशों में बहीखाते की जांच सही तरीके से न करने (अंकेक्षण विफलता) के बढ़ते मामलों के बीच अंकेक्षण सेवाओं के 'राष्ट्रीयकरण' के प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई है। हालांकि उद्योग जगत में वित्तीय दबाव अथवा धोखाधड़ी के हरेक मामले में अंकेक्षकों की निगरानी संबंधी भूमिका जांच के घेरे में आती है। आईएलऐंडएफएस में मौजूदा वित्तीय संकट ऐसा ही एक मामला है और इससे समूह के मौजूदा एवं पिछले अंकेक्षकों की भूमिका सुर्खियों में आ गई है।

ब्रिटेन के लेखा उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए उपायों पर गौर करने वाले शिक्षाविदों के समूह का नेतृत्व करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के प्रोफेसर (लेखा एवं वित्त) प्रेम सिक्का ने कहा, 'शिक्षा सहित हरेक स्तर पर अंकेक्षकों के साथ समस्या है।' उन्होंने कहा कि अंकेक्षण प्रथाओं में सुधार लाने और अंकेक्षण उद्योग को कहीं अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सरकार का दृष्टिकोण बहुआयामी होना चाहिए।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के पूर्व अध्यक्ष अमरजीत चोपड़ा ने कहा, 'बहीखाते की जांच सही तरीके से न करने के दो सबसे महत्त्वपूर्ण कारकों में अंकेक्षकों की आजादी का अभाव और जाहिर तौर पर लालच है।' विशेषज्ञों का कहना है कि अंकेक्षकों को महज निगरानीकर्ता मानने की अवधारणा अब पुरानी हो चुकी है। चोपड़ा ने कहा, 'अब हमें उस ओर बढ़ने की जरूरत है जहां अंकेक्षक समय पर यानी समस्या उजागर होने से काफी पहले चेतावनी देता हो।'

हालांकि लेखा विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए वैधानिक अंकेक्षण के दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि अंकेक्षकों को प्रबंधन के आकलन की जांच करते समय पेशेवर संशयवाद को कहीं अधिक लागू करना चाहिए और इसके लिए कंपनियों को अपने आकलन एवं अनुमानों के लिए कहीं अधिक ठोस खुलासे करने की जरूरत होगी। इसी प्रकार, चिंता संबंधी संकेतकों के प्रति समय रहते सचेत करने के लिए नियामकों को भी दिशानिर्देश मुहैया कराने की जरूरत होगी।

> लेखा फर्मों पर गैर-अंकेक्षण राजस्व बढ़ाने के बढ़ते दबाव के बीच अंकेक्षकों की आजादी बहस का मुद्दा बन गई है

लेखा फर्मों पर गैर-अंकेक्षण राजस्व बढ़ाने के बढ़ते दबाव के बीच अंकेक्षकों की आजादी बहस का मुद्दा बन गई है। चोपड़ा ने कहा, 'हर आकार की फर्म अंकेक्षकों की आजादी का अपेक्षित स्तर को बरकरार रखने में विफल रही है।' हालांकि बिग फोर के मामले में यह कहीं अधिक स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि लेखा फर्मों के साथ उनका वित्तीय संबंध भी समान नेटवर्क के तहत आता है। अधिकतर विशेषज्ञों ने माना कि आगे चलकर अंकेक्षण पेशे के लिए फर्मों को अंकेक्षण एवं परामर्श सेवाओं में ढांचागत तौर पर विभाजित करना पड़ेगा।

यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के प्रोफेसर (बिजनेस ऐंड पब्लिक पॉलिसी) कार्तिक रमन्ना ने कहा, 'अंकेक्षण और परामर्श सेवाओं को अलग करना नियामकों के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। परामर्श सेवाओं के लिए अंकेक्षकों का दिमाग जांचकर्ता के बजाय दोस्ताना हो जाता है। यह पूंजी बाजार के लिए उपयोगी नहीं है।'

लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर अमल करना आसान नहीं होगा। चोपड़ा ने कहा, 'लगभग 75 फीसदी भारतीय अंकेक्षण फर्मों में तीन से कम पार्टनर हैं।' इसके अलावा छोटे शहरों एवं कस्बों में ऐसी तमाम अंकेक्षण फर्म हैं जो अपने ग्राहकों को कर संबंधी सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं की पेशकश करती हैं।

चोपड़ा ने कहा, 'इससे काफी हद तक अंकेक्षकों की आजादी प्रभावित होती है। इसलिए विशेष सेवाओं की अवधारणा को बढ़ावा दिए जाने की तत्काल जरूरत है।'

इसके अलावा अंकेक्षण कार्यों में प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकी की तैनाती भी एक मुद्दा है। एसआर बाटलीबॉय ऐंड कंपनी के राष्ट्रीय निदेशक एवं पार्टनर (एश्योरेंस सेवा) सुधीर सोनी ने कहा, 'कई क्षेत्रों में सक्रिय फर्म अंकेक्षकों को जटिल कारोबारी माहौल में अंकेक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी एवं एनालिटिक्स जैसे विशेष कौशल उपलब्ध कराती है। लेकिन केवल अंकेक्षण करने वाली फर्म इन कौशलों से संपन्न प्रतिभाओं को आकर्षित करने में समर्थ नहीं होगी' अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय उद्योग जगत को भी कारोबारी निर्णयों के लिए कहीं अधिक जबावदेह बनने की जरूरत है।

> 'बहीखाते की जांच सही तरीके से न करने के दो सबसे महत्त्वपूर्ण कारकों में अंकेक्षकों की आजादी का अभाव और जाहिर तौर पर लालच है'
>
> **अमरजीत चोपड़ा**
> पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई

कई अंकेक्षकों ने अंकेक्षण कार्यों में विरोधाभास को उजागर किया है। किसी अंकेक्षण खाते से इस्तीफा देने वाले अंकेक्षक को उसके लिए कारण बताने की जरूरत होती है लेकिन उन कंपनियों के प्रबंधन उसी स्तर की जांच नहीं करती हैं। चोपड़ा ने कहा, 'जिन कंपनियों के अंकेक्षक इस्तीफा दे देते हैं उनके प्रबंधन से भी सवाल पूछे जाने चाहिए।' पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान कंपनियों के अंकेक्षकों के इस्तीफे के कई मामले सामने आए हैं। अधिकतर मामलों में प्रबंधन और अंकेक्षकों के बीच मतभेद के कारण इस्तीफे दिए गए।

जाहिर तौर पर अंकेक्षण सेवाओं के लिए नवनियुक्त नियामक नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को अंकेक्षकों को अधिक अधिकार देने पर ध्यान देने की जरूरत है।

RUSHIL
DECOR LIMITED

CIN : L25209GJ1993PLC019532

Regd. Office: S. No.125, Near Kalyanpura Patia, Vill. Itla, Gandhinagar Mansa Road, Tal. Kalol, Dist. Gandhinagar -382845, Gujarat, India
Corporate Office: Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off Sindhu Bhavan Road, Shilaj, Ahmedabad-380058, Gujarat, India.
Ph.:+91-079-61400400 Fax :+91-079-61400401 E-mail : cs@virlaminate.com Web site : www.rushil.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2019

(₹ in Lacs)

Particulars	Quarter ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter ended 31.03.2018 (Audited)
Total income from operations	8653.94	34374.21	8808.48
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,Exceptional and/or Extraordinary items)	629.64	2291.94	1331.90
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	629.64	2291.94	1331.90
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	383.46	1433.50	903.77
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	392.80	1430.15	916.34
Equity Share Capital	1493.13	1493.13	1471.75
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	19099.04	19099.04	15594.11
Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not Annualised)			
1.Basic :	2.57	9.62	6.21
2.Diluted :	2.57	9.62	6.21

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the company's website www.rushil.com

For, Rushil Décor Limited
Ghanshyambhai A. Thakkar
Chairman
DIN:00208843

Place: Ahmedabad
Date: 18th May, 2019

VIR LAMINATE
VIR MDF

MISHRA DHATU NIGAM LIMITED
(A Govt of India Enterprise) (A Mini Ratna-1 Company)
Registered & Corporate Office: PO Kanchanbagh, Hyderabad-500058
Website: www.midhani-india.in, Email ID: secretary@midhani-india.in

Notice

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 33 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, i.e., on 29.05.2019 inter alia to approve and take on record the Financial Results (Audited) for the quarter and year ended 31st March, 2019 and also to consider recommendation of final Dividend, if any, for the FY 2018-19,.
After the conclusion of the meeting, the outcome thereof will be available on the company website and also on BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

For Mishra Dhatu Nigam Limited
Sd/-
Paul Antony
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 18.05.2019

फॉर्म-जी
अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

संबंधित विवरण

1. कॉरपोरेट देनदार का नाम	स्ट्राईड ऑटोपार्टस् लि.
2. कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	26-11-2010
3. उस ऑथेरिटी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, नई दिल्ली
4. कॉरपोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U34300DL2010PLC210810
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालय: एफ–16, ट्रेवेनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शेख सराय – I, नई दिल्ली – 110017 वर्क्स : प्लॉट नं. एसपी–255, कहरानी औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी एक्सटेंशन के पास, भिवाड़ी, राजस्थान–301019, भारत
6. कॉरपोरेट देनदार के सम्बंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	08-01-2019
7. अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि	20.05.2019 (पूर्व में 10.04.2019, 18.03.2019)
8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:	कोड की धारा 25(2)(एच) के तहत संभावित समाधान आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें : http://witworthipe.com/sapl, cirp.sapl@gmail.com से डाउनलोड / प्राप्त की जा सकती हैं।
9. धारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानक निम्नलिखित पर उपलब्ध है:	धारा 29 ए के तहत लागू अयोग्यता के मानदंड http://witworthipe.com/sapl, cirp.sapl@gmail.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं IBBI की वेबसाइट https://ibbi.gov.in/legal-framework/updated पर भी उपलब्ध है
10. अभिरूचि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि	15.06.2019 (पूर्व में 10.05.2019, 02.04.2019)
11. संभावी समाधान आवेदकों के अनंतिम सूची निर्गमन की तिथि	25.06.2019 (पूर्व में 20.05.2019, 12.04.2019)
12. अनंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि	30.06.2019 (पूर्व में 25.05.2019, 17.04.2019)
13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गमन की तिथि	09.07.2019 (पूर्व में 05.06.2019, 27.04.2019)
14. संभावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्गमन की तिथि	30.06.2019 (पूर्व में 25.05.2019, 17.04.2019)
15. समाधान योजना के लिए अनुरोध, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	अनंतिम / अंतिम सूची में शामिल संभावित रिजॉल्यूशन आवेदक को मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन और क्र.सं. 21 के अंतर्गत ई–मेल के माध्यम से रिजॉल्यूशन प्लान के लिए अनुरोध के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस तरह के आवेदक(ओं) द्वारा गोपनीयता प्रदान करने के बाद प्रदान किया जाएगा।
16. समाधान योजना को जमा करने की अंतिम तिथि	30.07.2019 (पूर्व में 25.06.2019, 17.05.2019)
17. समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजनाओं को जमा करने का तरीका	रिजॉल्यूशन आवेदक को रिजॉल्यूशन प्लान को प्रोफेशनल ई–मेल के माध्यम से और भौतिक रूप से / डाक द्वारा सीलबंद लिफाफे में क्लॉज 21 में या उससे पहले दिए गए पते पर जमा करेंगे रिजॉल्यूशन प्लान जमा करने की अंतिम तिथि, जैसा कि ऊपर दिए गए खंड 16 में वर्णित है
18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी के पास समाधान योजना को जमा करने की अनुमानित तिथि	21-08-2019
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	**देवेन्द्र सिंह** IBBI/IPA-002/IP-N00001/2016-17/10001
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई–मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	नाम: देवेंद्र सिंह पता: ए टी एस ग्रीन्स पैराडाइज़, फ्लैट नं. 02054, टॉवर – 2, प्लॉट नं. जी एच–03, सैक्टर–सी एच आई–04, ग्रेटर नोएडा, यू. पी–201308 ई–मेल : dev_singh2006@yahoo.com
21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	पता: सी–124, भूतल, लाजपत नगर–I, नई दिल्ली–110024 ई–मेल : cirp.sapl@gmail.com
22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास उपलब्ध है	**नाम : देवेन्द्र सिंह, रिजॉल्यूशन पेशेवर** **वेबलिंक :** http://witworthipe.com/sapl, ईमेल: dev_singh2006@yahoo.com cirp.sapl@gmail.com
23. फॉर्म–जी के प्रकाशन की तिथि	20-05-2019 (पूर्व में, 10.04.2019, 18-03-2019)

नोटः क्लॉज 18 में तारीख इन्सॉल्वेंसी के नियम 40 के साथ पठित धारा 12 के तहत 90 दिनों तक CIRP अवधि के विस्तार के लिए अनुमोदन के अधीन है और दिवाला बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 लेनदारों की समिति और माननीय सहायक प्राधिकरण द्वारा

देवेन्द्र सिंह,
समाधान प्रोफेशनल, स्ट्राईड ऑटोपार्टस् लि. के मामले में
(कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया)
रजि. नंबर: IBBI/IPA-002/IP-N00001/2016-17/10001,
पता: एटीएस ग्रीन्स पैराडिसो, फ्लैट नं. : 02054, टॉवर – 2, प्लॉट नं. : जीएच–03, सैक्टर – सी एच आई–04, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201308,
ई–मेल : dev_singh2006@yahoo.com, cirp.sapl@gmail.com,
मो.: 9810331877, 9810339416

तिथिः 20.05.2019
स्थानः नई दिल्ली

నోటీసులివ్వగానే పరార్

- చట్టంలోని వెసులుబాటే వారికి ఆయుధం
- మత్తయ్య నుంచి రవిప్రకాశ్ దాకా ఇదే తీరు
- కొంతకాలానికి కేసు కోల్డ్ స్టోరీజీలోకి..
- గత కేసులే ఇందుకు నిదర్శనం

సాక్షి, హైదరాబాద్: ఓటుకు కోట్లు కేసు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన కేసు. ఈ కేసులో నిందితులందరికీ నోటీసులు జారీ చేసినా, దాదాపు అందరూ పోలీసుల విచారణకు వెంటనే రాలేదు. రేపని.. మాపని.. ఆరోగ్యం బాగాలేదని.. అందుబాటులో లేమంటూ.. రకరకాల కారణాలు చెప్పి విచారణను వీలైనంత జాప్యం చేశారు. ఈలోగా కేసు గురించి అంతా మర్చిపోయారు. ఇది ఇలాంటి కేసుల్లో ఇరుక్కునే వారికి ప్రాథమిక పాఠంగా మారింది. విచారణను వీలైనంత జాప్యం చేస్తే.. కేసు గురించి అంతా మర్చిపోతారన్న సంకేతాలు బలంగా వెళ్లాయి. అది మొదలు.. ఇలాంటి కేసుల్లో చిక్కుకున్న వారెవరూ పోలీసు విచారణ అంటే పెద్దగా బెదిరిపోవడం లేదు.

వెసులుబాటే ఆసరా..

ఓటుకు కోట్లు కేసులో నిందితుడు మత్తయ్య నుంచి ఫోర్జరీ కేసులో ఇరుక్కున్న టీవీ9 మాజీ సీఈఓ రవిప్రకాశ్ వరకు అందరూ ఇదే పోకడ అనుసరిస్తుండటం గమనార్హం. విచిత్రంగా ఓటుకు కోట్లు, ఐటీ గ్రిడ్ డేటా చౌర్యం కేసులు ఆరంభంలో తీవ్ర సంచలనం రేపాయి. కానీ, కాలక్రమంలో రెండు కేసుల్లో ఇంత వరకూ పెద్దగా పురోగతి లేకపోవడం, నత్తకు తాతలా దర్యాప్తు సాగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ మూడు ఏడేళ్లలోపు శిక్ష పడే నేరాలే కావడంతో పోలీసులు నిబంధనల ప్రకారం.. సీఆర్పీసీ 160 కింద నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. వీటిని అందుకున్న నిందితులు కేసు దర్యాప్తును ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో విచారణకు డుమ్మా కొడుతున్నారు. తెలంగాణలో ఉంటే పోలీసులు ఎలాగైనా అరెస్టు చేస్తారన్న ఉద్దేశంతో పొరుగు రాష్ట్రాలకు పారిపోతున్నారు. వీరంతా ఏపీకి వెళ్లడం, అక్కడి అధికార టీడీపీ నిందితులకు మద్దతు పలకడం విశేషం. ఒకవేళ తెలంగాణ పోలీసులు వెళ్లినా.. వారికి నిందితులను అరెస్టు చేయడం కష్టం అవుతుండటంతో ఈ కేసుల్లో విపరీతమైన జాప్యం నెలకొంటోంది. మత్తయ్య బాటలో ఏపీకి పారిపోయిన ఐటీ గ్రిడ్ అశోక్, రవిప్రకాశ్ ఆచూకీని ఇంతవరకూ పోలీసులు కనిపెట్టలేకపోయారు. వాస్తవానికి క్లిష్టమైన కేసుల చిక్కుముడులు విప్పడంలో, వివిధ నేరాల్లో నిందితులకు త్వరగా శిక్షలు పడేలా చేయడంలో రాష్ట్ర పోలీసులు అనేక ప్రశంసలు, పురస్కారాలు అందుకుంటున్నారు. కానీ, ఈ మూడు కేసుల్లో మాత్రం దర్యాప్తు తీరు ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుగా సాగడం గమనార్హం.

మిశ్రధాతు నిగమ్ లిమిటెడ్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ) (మినిరత్న-1 కంపెనీ)
రిజిస్టర్ & కార్పొరేట్ కార్యాలయం: PO కంచన్‌బాగ్, హైదరాబాద్ -500058
వెబ్‌సైట్: www.midhani-india.in ఇమెయిల్ ID: secretary@midhani-india.in

ప్రకటన

SEBI (LODR) రెగ్యులేషన్స్, 2015 లోని రెగ్యులేషన్ 33 & 47తో చదువబడే రెగ్యులేషన్ 29ను అనుసరిస్తూ 31 మార్చి 2019తో ముగిసిన త్రైమాసిక మరియు సంవత్సరానికి ఇతర విషయాలతో పాటు ఆర్థిక ఫలితాల (ఆడిట్ చేసినవి)ను ఆమోదించి మరియు రికార్డ్‌లోకి తీసుకొనుటకు మరియు 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఫైనల్ డివిడెండ్ ఏదైనా ఉంటే, సిఫారసు పరిశీలించేందుకు కూడా కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డ్ సమావేశం బుధవారం అనగా 29-05-2019న నిర్వహించేందుకు షెడ్యూలు చేయబడిందని ఇందుమూలంగా నోటీసు ఇవ్వడమైనది.
సమావేశం ముగిసిన తరువాత, దాని ఫలితం వరుసగా కంపెనీ వెబ్‌సైట్ మరియు BSE & NSE వెబ్‌సైట్లు www.bseindia.com మరియు www.nseindia.com లో కూడా లభిస్తుంది.

మిశ్రధాతు నిగమ్ లిమిటెడ్ తరఫున
సం/- పాల్ ఆంటోని
కంపెనీ సెక్రటరీ & కాంప్లియన్స్ ఆఫీసర్

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేది: 18.05.2019

విద్యుదాఘాతంతో కార్మికుడి మృతి

గట్టు (గద్వాల): జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం మాచర్లలో ఆదివారం ఉదయం విద్యుదాఘాతంతో మాచర్ల శివరాం(39) అనే కాంట్రాక్టు కార్మికుడు మృతి చెందాడు. మాచర్ల మాజీ సర్పంచ్ పద్మావతి భర్త అయిన శివరాం గట్టు విద్యుత్ సబ్‌స్టేషన్‌లో కాంట్రాక్టు కార్మికుడు. కాగా, శనివారం అర్ధ రాత్రి ఉరుములు, మెరుపుల కారణంగా గట్టులో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. విద్యుత్‌ను పునరుద్ధరించే క్రమంలో పంచాయతీ పక్కనున్న ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ వైర్లను సరిచేసేందుకు శివరాం ప్రయత్నిస్తుండగా విద్యుదాఘాతానికి గురై తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. చికిత్స నిమిత్తం గద్వాల ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే మృతి చెందాడు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని మాచర్ల గ్రామస్తులు, బంధువులు ఆందోళన చేశారు.

‘పన్నులశాఖ గెజిటెడ్’ అధ్యక్షుడిగా వెంకటయ్య

సాక్షి, హైదరాబాద్: వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం అధ్యక్షుడిగా బి.వెంకటయ్య ఎన్నికయ్యారు. నగరంలోని ఈ సంఘం కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆదివారం జరిగిన ఎన్నికల్లో వెంకటయ్య ప్యానెల్ విజయం సాధించింది. ఈ ప్యానెల్ నుంచి పోటీచేసిన సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు టి.శ్రీనివాస్, క్రీడల కార్యదర్శి పి.రామలక్ష్మయ్య, కార్య వర్గ సభ్యులు బి.రాజు, ఎ.నరేందర్ విజయం సాధించారు. ప్రధాన కార్యదర్శిగా దేవేందర్, గిరిధర్, రమేష్, నాగేందర్ తదితరులు ఇతర స్థానాల్లో గెలిచారు. ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిగా అడిషనల్ కమిషనర్ జె.లక్ష్మీనారాయణ, సహాయ ఎన్నికల అధికారులుగా డిప్యూటీ కమిషనర్లు రామకృష్ణ, కె.రవి వ్యవహరించారు. వెంకటయ్య విజయం పట్ల టీజీవో అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ, టీఎన్జీవో అధ్యక్షుడు రవీందర్‌రెడ్డి, రాజేందర్, టీజీవో నగర అధ్యక్షులు జి.వేంకటేశ్వర్లు, రవీందర్‌కుమార్, కృష్ణయాదవ్, అశోక్‌కుమార్ అభినందనలు తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాణిజ్యపన్నుల శాఖ కమిషనరేట్ పరిధిలోని 12 డివిజన్లలో ఉన్న 348 ఓట్లకు 318 ఓట్లు పోలయ్యాయి.

టీఎంఎం కన్వీనర్‌గా పిల్లి సుధాకర్

సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ మాల మహానాడు (టీఎంఎం) రాష్ట్ర కన్వీనర్‌గా మహబూబాబాద్ జిల్లాకు చెందిన పిల్లి సుధాకర్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు టీఎంఎం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అద్దంకి దయాకర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. భైరి రమేశ్ (హైదరాబాద్), దార సత్యం (రంగారెడ్డి), కరికె శ్రీనివాస్(సిద్దిపేట), గోలి సైదులు(నల్లగొండ), మేడి అం జయ్య (కరీంనగర్), కనిగిరి రవి (మేడ్చల్), తుమ్మల రవికుమార్ (గద్వాల), కె.సాయిగిరి (హైదరాబాద్)లను రాష్ట్ర కోకన్వీనర్లుగా విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో నిర్ణయించినట్లు దయాకర్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

పెళ్లికి వెళ్లి అనంత లోకాలకు..

- ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన బొలేరో
- అక్కడికక్కడే ఇద్దరి మృతి
- మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు
- సిద్దిపేటజిల్లాలో ప్రమాదం

ప్రమాదానికి కారణమైన బొలేరో వాహనం రోడ్డు కింద బోల్తా పడిన దృశ్యం

కొండపాక(గజ్వేల్): రాజీవ్ రహదారి మరోసారి రక్తసిక్తమైంది. ఓ ద్విచక్ర వాహనాన్ని అతివేగంగా వచ్చిన బొలేరో వాహనం ఢీకొట్టడంతో బావామరదలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరదలు చెయ్యి తెగిపోయి సుమారు 20 గజాల దూరంలో పడిపోయింది. ఆదివారం సిద్దిపేట జిల్లా కొండపాక మండలంలోని కుకునూరుపల్లి పోలీస్‌స్టేషన్ ఎదురుగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వివరాలు... కొండపాక మండలంలోని తిమ్మారెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన కసిరెడ్డి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి కూతురు రవళి వివాహం కుకునూరుపల్లిలోని కోల ఆంజనేయులు ఫంక్షన్‌హాల్ జరిగింది. దుబ్బాక మండలంలోని రఘోత్తంపల్లికి చెందిన రెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి (35), వెంకట్‌రెడ్డి మేనమరదలు, తొగుట మండలం వేముల గట్టు గ్రామానికి చెందిన శేరిపల్లి సౌమ్య(12), దుబ్బాక మండలంలోని బొప్పాపూర్‌కు చెందిన వెంకట్‌రెడ్డి చెల్లెలు కవిత (28), ఆమె కూతురు శ్రీవిద్య(6)లు ద్విచక్ర వాహనంపై ఈ పెళ్లికి వచ్చారు. కాగా ఎండ వేడిమికి తట్టుకోలేక వారు స్థానిక వైద్యుని వద్దకు వచ్చి మందులు తీసుకుని మళ్ళీ ఫంక్షన్ హాల్‌కు బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో కుకునూరుపల్లి పోలీ స్టేషన్ ఎదురుగా ద్విచక్ర వాహనాన్ని యూటర్న్ చేస్తుండగా సిద్దిపేట నుంచి హైదరాబాద్ వైపునకు వెళుతున్న బొలేరో వాహనం అతి వేగంగా వచ్చి ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టి అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కన బోల్తా పడింది. దీంతో వెంకట్‌రెడ్డి, శేరిపల్లి సౌమ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కవిత, శ్రీవిద్యలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయాలైన కవిత, శ్రీవిద్యలను హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. బొలేరో వాహనం ఢీకొట్టడంతో సౌమ్య కుడి చెయ్యి తెగిపోయి సుమారు 20 గజాల దూరంలో పడిపోయింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఫంక్షన్ హాల్‌లోని బంధువులు, కుటుంబీకులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. దీంతో సుమారు అరగంటపాటు రాజీవ్ రహదారిపై ట్రాఫిక్ జామ్ అవడం తో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సౌమ్య తండ్రి హన్మంతరెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని మృతదేహాలను గజ్వేల్‌లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు ఎస్సై పరమేశ్వర్ తెలిపారు. ఈ సంఘటనతో వెంకట్‌రెడ్డి స్వగ్రామం రఘోత్తంపల్లి, సౌమ్య స్వగ్రామం వేముల గట్టులో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. సౌమ్య 8వ తరగతి చదువుతోందని, వెంకట్‌రెడ్డికి నెల పదిహేను రోజుల కిందట పాప జన్మించిందని బంధువులు తెలిపారు.